साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार 12-18 दिसंबर , 2022वर्ष-8, अंक-35

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणा-हर ग्राम पंचायत में रोजगार सहायक की नियुक्ति की जाएगी

सरपंचों का ढाई गुना बढ़ाया मानदेय, पंचायत को 25 लाख तक के काम का अधिकार

भोपाल। जागत गांव हमार

राजधानी भोपाल में नवनिर्वाचित सरपंचों का उन्मुखीकरण प्रशिक्षण सह सम्मेलन का आयोजन जंबूरी मैदान किया गया। इस अवसर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरपंचों से संवाद किया। सीएम ने कहा कि मैं आपको अधिकार देता हूं कि कोई भी जायज नाम बीपीएल की सूची में छूट गया हो, तो आप उसे भेजें, हम वो सभी नाम जोड़ेंगे। सीएम ने सरपंचों का मानदेय 1750 रुपए से बढ़ाकर ढाई गुना यानी 4,250 रुपए करने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं यह कर रहा हूं जिससे आपका खर्च निकल सके। सीएम ने घोषणा कि ग्राम पंचायत को प्रशासकीय स्वीकृति के अधिकार 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख किया जाएगा। वहीं, प्रत्येक ग्राम पंचायत में रोजगार सहायक की नियुक्ति की जाएगी। रोजगार सहायक के स्थानांतरण भी करेंगे। 15वें वित्त आयोग की राशि 1,472 करोड़ जारी कर दी गई है।

सरपंचों को सीख

- छोटे-मोटे झगड़े गांव के अंदर ही निपट जाएं और उसकी प्राथमिकी दर्ज न हो।
- पंचायत पदाधिकारी संवाद, समन्वय और संपर्क का उपयोग कर अच्छा कार्य करें।
- हम अपनी पंचायतों को भी स्वच्छ ग्राम पंचायत बनाने का प्रयास करें।
- आवास निर्माण का कार्य बिना लेन-देन के हो, सरकार भ्रष्टों को छोड़ेगी नहीं।
- बेटियों के प्रति आदर का भाव हो, हम अपने ग्राम में बेटियों को सम्मान दें।
- ग्रामों का मास्टर प्लान बनाएं, पदाधिकारी ग्रामों के कार्य का निर्धारण करेंगे।
- ग्राम को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रयास करें, पंचायतों में सीधे राशि पहुंचेगी।

एसओआर में परिवर्तन होगा

सीएम ने गांव को हरा भरा करने के लिए पौधा रोपण करने की भी अपील की। सरपंचों की तरफ से निर्माण लागत को लेकर एसओआर को बदलने की मांग की। इस पर सीएम ने कहा कि आज हम फैसला कर रहे हैं कि एसओआर में परिवर्तन किया जाएगा और पिछली बाजार दर से नया एसओआर बनाया जाएगा। वास्तविक खर्चा के अनुसार काम हो जाए।

नामांतरण का अधिकार पंचायत को

सीएम ने कहा कि कपिलधारा योजना में कुआं खोदने की अनुमति आपको दी जाएगी। खेतों की सुदूर सड़क संपन्न योजना हम फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। राज्य वित्त की जो राशि आती है, उसे हम आपके हिसाब से जारी करने का काम करेंगे। नामांतरण जैसे मामलों में पंचायत के पास अधिकार आ जाएं। सरपंचों की तरफ से सीएम हेल्पलाइन पर झूठी शिकायत कर करने का मुद्दा उठाया और ऐसी फर्जी शिकायत करने वालों के खिलाफ एफआईआर करने की मांग की गई। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं यह व्यवस्था करूंगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

अहम घोषणाएं

- सरपंचों का मानदेय 1750 रुपए से बढ़ा कर 4250 रुपए प्रतिमाह होगा।
- प्रदेश में नया एसओआर बनेगा। शीघ्र ही यह सूची जारी की जाएगी।
- प्रदेश की पंचायतों के सचिवों के रिक्त पदों की पूर्ति की जाएगी।
- जीआरएस को एक से दूसरी पंचायत में स्थानांतरित किया जाएगा।

सम्मेलन के प्रमुख बिंदु

- जनता की भागीदारी होगी तो सफलता मिलेगी।
- मिलकर लोगों तक उनके अधिकार पहुंचाएंगे।
- ग्राम सभा की बैठकें नियमित रूप से हों।
- ग्रामीणों को उनके अधिकारों से वंचित न रखें।
- पंचायत पदाधिकारी बिना अध्ययन के हस्ताक्षर न करें।
- व्यवस्था में सुधार के लिए जरूरी सुझाव भी जरूर दें।
- सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के संकल्प अनुरूप कार्य करें।
- सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तन्मयता से कार्य करें।
- पंचायत पदाधिकारी जन-अपेक्षाओं पर गंभीर और सदैव संयमित रहें।
- पंचायत पदाधिकारी दिन और सप्ताह की समय-सारणी बना कर कार्य करें।

अपात्र किसानों को अब नहीं मिलेंगे सालाना 6000 रुपए, केंद्र ने 11वीं किस्त 11.45 करोड़ किसानों को भेजी गई थी

» फर्जी को पहचानने के लिए जमीन के रिकॉर्ड का आधार से मिलान किया जा रहा

» आधार को चौथे डिजिटल फिल्टर से मिलाया, तो 1.86 करोड़ किसान हुए कम

पीएम सम्मान निधि से 1.86 करोड़ फर्जी किसान बाहर

भोपाल। जागत गांव हमार

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को करोड़ों किसानों को आर्थिक मजबूती प्रदान की है। योजना के जरिए किसानों के बैंक खाते में हर साल 6,000 रुपए दिए जाते हैं। ये रकम हर चार महीने के अंतराल पर दो-दो हजार रुपए की तीन किस्तों में किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। कई लोगों ने इस स्कीम का गलत तरीके से भी लाभ लिया है, जिनके खिलाफ सरकार ने सख्ती कार्रवाई की है। यही वजह है कि पिछले 6 महीने में पीएम किसान योजना से करीब 1.86 करोड़ फर्जी किसान बाहर हो गए हैं। इन किसानों को अपात्र घोषित कर दिया गया है। 11 वीं किस्त के बाद से ही कई ऐसे मामले सामने आ रहे थे, जिसमें कुछ किसान अपात्र होने के बावजूद दो-दो हजार रुपए की किस्तों को लाभ उठा रहे थे। इन किसानों की पहचान करना भी आसान नहीं था, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा ई-केवाईसी वेरिफिकेशन और लैंड सीडिंग और कई तकनीकी फिल्टर्स के जरिए इन गैर-लाभार्थियों को पकड़कर बाहर कर दिया गया है।

इस तरह चोरी पकड़ती है सरकार

पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर किसानों की लिस्ट और उनका डेटा समय-समय पर अपडेट किया जाता है। ये डाटा राज्य सरकार ही केंद्र सरकार तक पहुंचाती है। इसके बाद किसानों की ये जानकारी कुछ सरकारी संस्थाओं को भी सत्यापन के लिए भेजी जाती है, जिसमें आयकर विभाग भी शामिल है, जो अपने अंडर आने वाले किसानों की जानकारी लेता है। इसके बाद बैंक खाता और आधार कार्ड का लिंक करने के लिए किसानों का डाटा डेटा नेशनल पेमेंट कार्पोरेशन को भी भेजा जाता है। इन संस्थानों के अलावा पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम और आधार नंबर की पुष्टि के लिए यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी शामिल हैं।

उत्तर भारत में भी घटी किसानों की संख्या

केंद्र सरकार ने 12वीं किस्त जारी करने से पहले ही ई-केवाईसी यानी किसान का बैंक-आधार लिंक करने वाली प्रोसेस को अनिवार्य कर दिया था। इसे सरकार ने चौथा डिजिटल फिल्टर बताया है। जब किसानों ने इस डिजिटल फिल्टर का इस्तेमाल किया तो देशभर से लाभार्थी किसानों की संख्या कम होने लगी। इससे ये भी सामने आया कि कितनी बड़ी संख्या में अपात्र किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ मिल रहा था। इस मामले में उत्तर भारत से भी मिले-जुले रुझान सामने आए। यहां उत्तर प्रदेश में आधार लिंक का चौथा फिल्टर इस्तेमाल करते ही 58 लाख किसान कम हो गए। पंजाब में 17 लाख किसानों से घटकर 2 लाख ही रह गए। इसी के साथ-साथ 5 और राज्यों में भी बड़े पैमाने पर गैर-लाभार्थी किसानों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है।

गांव-गांव में होगी पहचान | योजना में अभी भी कई किसान ऐसे हैं, जिन्होंने सरकार के डर से या जागरुकता की कमी के कारण ई-केवाईसी वेरिफिकेशन नहीं करवाया है। इसलिए उन्हें 12वीं किस्त नहीं मिल पाई है। केंद्र ने राज्य सरकारों को फरमान जारी किया है और गांव-गांव टीम भेजकर असली लाभार्थियों की पहचान करने के निर्देश भी दिए हैं।

1.86 करोड़ कम हुए किसान

योजना के ताजा आंकड़े बताते हैं कि देशभर के 10.45 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 11वीं किस्त के 2,000 रुपए जारी हुए थे, लेकिन 12वीं किस्त तक किसानों की संख्या सिर्फ 8.58 करोड़ ही रह गई। ये आंकड़ा बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि देश के 5 राज्यों से प्रति 10 से 15 लाख किसान बाहर हुए हैं। इस राज्य में पंजाब (14,88760), केरल (14,59,806), राजस्थान (14,29,402), उड़ीसा (11,51,262) और महाराष्ट्र (10,87,791) शामिल हैं। तमिलनाडु से 9.85 लाख किसान, झारखंड से 9.38 लाख किसान, गुजरात से 6.78 लाख किसान, छत्तीसगढ़ से 6.65 लाख किसान और जम्मू-कश्मीर से भी 6.59 लाख किसानों को अब सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलेगा।

इन राज्यों में बढ़े लाभार्थी

प्रस्तुत आंकड़ों से सामने आया है कि कर्नाटक में 85.947 लाख किसान, नागालैंड में 13.142 लाख किसान, मणिपुर में 2.170 लाख किसान, मिजोरम में 913 और लक्षदीप में 842 किसानों की संख्या बढ़ी है।

शिल्पकारों की उम्मीद फाइलों से नहीं निकल पाई बाहर

हैंडीक्राफ्ट की वेबसाइट में रीवा के सुपारी कारीगर नहीं

अस्त होने की कगार पर रीवा की सुपारी हस्तशिल्प कला

रीवा। जागत गांव हमार

मध्य प्रदेश के रीवा के रहने वाले 47 साल के शिल्पकार अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी हैं, जो बीटल नट यानी नन्हीं सुपारी से कलाकृतियां बनाने का काम करती आई हैं। राकेश के अनुसार 1932 की बात है जब उनके दादा रामसिया कुंदर रीवा रियासत के महाराजा गुलाब सिंह के दरबार में दरबारियों को पान और सुपारी परोसते थे। उनके दादा को एक छोटा सा सिंदूर का डब्बा बनाने का विचार आया। उन्होंने उसे बनाया और दरबार में सभी लोगों के बीच बांट दिया। रॉयल्टी ने इसे खासा पसंद किया और मेरे दादा को खुश होकर पचास रुपए का इनाम भी दिया गया। तब से कुंदर परिवार सुपारी से कलाकृतियां बनाने में लगा है। राकेश खुद पिछले 32 सालों से इस कला से जुड़े हैं। राकेश के पास लक्ष्मी और गणेश की मूर्तियां हमेशा तैयार और उपलब्ध रहती हैं। लेकिन ताजमहल, छोटे लैंप, जानवरों की मूर्तियां आदि जैसी अन्य चीजें ऑर्डर पर ही बनाते हैं। राकेश के चाचा दुर्गेश कुंदर भी इस तरह की कलाकृति बनाने का काम करते हैं। 50 साल के दुर्गेश ने बताया कि मैंने 15 साल की उम्र में नक्काशी करना शुरू कर दिया था। इस काम में समय लगता है। उन्होंने कहा कि यह कहना मुश्किल है कि हम हर महीने कितना कमा लेते हैं। दरअसल, यह ऑर्डर पर निर्भर करता है। हम 50 फीसदी लाभ मार्जिन पर काम करते है। दुर्गेश ने कहा, लेकिन फिलहाल तो शिल्प का भविष्य अंधकारमय दिख रहा है। उन्हें डर है कि आने वाली युवा पीढ़ी इस हुनर को आगे ले जाने या अपनाने के लिए तैयार नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हमने सरकार के सामने एक प्रस्ताव रखा था कि हम उन लोगों को शिल्प सिखाएंगे जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भी शिल्प को बढ़ावा देने की सिफारिश की थी। लेकिन यह सब कुछ फाइलों में ही सिमट कर रह गया है। दुर्गेश ने बताया कि 1932 से एक अकेला परिवार इस सुपारी कला का संरक्षक रहा है, लेकिन शिल्प को जिंदा बनाए रखने में हमारी मदद करने के लिए कोई सहायता नहीं मिल रही है। अगर हमें एनआईटी आदि जैसे संस्थानों तक पहुंच दी जाती, तो हम कला को और आगे तक ले जा सकते हैं। लेकिन आज इस कला की जो स्थिति है, अगर आगे भी वैसी ही बनी रहती है, तो मैं निश्चित रूप से युवा पीढ़ी को इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे किसी ऐसी चीज पर काम करके अपनी आंखों की रोशनी खराब करें जो सरकारी मदद या प्रोत्साहन के योग्य नहीं है। इस काम को करने से मिलने वाला पैसा सिर्फ गुजारा करने तक के लिए काफी है। उन्होंने कहा कि अपने इस हुनर को दिखाने के लिए हम सिर्फ ग्राहकों के आने का इंतजार करते रहते हैं।

राकेश खुद पिछले 32 सालों से इस कला से जुड़े हैं। राकेश के पास लक्ष्मी और गणेश की मूर्तियां हमेशा तैयार और उपलब्ध रहती हैं। लेकिन ताजमहल, छोटे लैंप, जानवरों की मूर्तियां आदि जैसी अन्य चीजें ऑर्डर पर ही बनाते हैं।

शिल्पकारों की मदद के प्रयास किए गए हैं। हम इस शिल्प को एक जिला एक उत्पाद कैटेगरी में शामिल करना चाहते थे, लेकिन इस श्रेणी में शामिल करने के लिए जिस तरह के शिल्प की जरूरत होती है वो इस खासियत इस शिल्प में नहीं है। उन्हें व्यापक हस्तशिल्प समूह विकास योजना में शामिल करने का भी प्रयास किया गया। लेकिन शिल्प में शामिल पांच परिवार एकजुट नहीं थे और इसलिए हम आगे नहीं बढ़ सके।
यूबी तिवारी, महाप्रबंधक, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, रीवा

सुपारी से खिलौने बनाना

शिल्पकार ने बताया कि इसके लिए सबसे पहले बाजार में मिलने वाली सबसे बड़ी सुपारी का चयन किया जाता है। फिर एक बिजली के औजार से वह सुपारी को उस खिलौने के अलग-अलग हिस्सों में तराशते हैं जिन्हें बनाने का उनका मन है और अंत में उन हिस्सों को एक साथ चिपका दिया जाता है। इस तरह से एक पर्यावरण के अनुकूल सुपारी खिलौना बनकर तैयार होता है। खिलौने या मूर्ति की कीमत उसके आकार पर निर्भर करती है। इनकी कीमत 600 रुपए से ज्यादा हो सकती है। वे आम तौर पर ऐसे टुकड़े बनाते हैं जो 13 इंच तक लंबे होते हैं। अगर इससे बड़ा कुछ दुर्लभ बनाना है, तो उसे सिर्फ ऑर्डर पर ही तैयार किया जाता है।

लॉकडाउन से थम गई आमदनी

कुंदर परिवार के मुताबिक, इस काम में काफी समय लगता है। घंटों तक फर्श पर बैठे रहना, एक छोटे सी सुपारी पर बारीकी से नजर बनाए रखना, बिजली के उपकरण को सावधानी से इस्तेमाल करना और छोटी सी आकृति पर विवरण को उकेरना उनकी इस मेहनत में शुमार है। रीवा में आयोजित सभी सरकारी और निजी प्रदर्शनियों में हमारी मूर्तियों को स्मृति चिन्ह के रूप में दिया जाता है और आयोजक हमेशा पहले से ही उन्हें ऑर्डर कर देते हैं। कुंदर परिवार को उनके शिल्प से बहुत पहचान मिली है, लेकिन महामारी के समय उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा था। लॉकडाउन के दौरान हमारी कमाई लगभग रुक गई थी। लेकिन अब चीजें वापस सामान्य हो रही हैं। इस दिवाली में हमने अपने हाथों से बनाई गई लगभग 120 कलाकृति बेची थीं। जैसे-जैसे आयोजन फिर से शुरू हो रहे हैं, हम अपने काम और कमाई, दोनों के बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं।

शिल्पकार को पहचान चाहिए

डेवलपमेंट मिनिस्टर (हैंडीक्राफ्ट) की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, देश में 6.89 मिलियन शिल्पकार हैं। 2020-21 में भारत ने 3,459.74 अमेरिकी डॉलर के हस्तशिल्प का निर्यात किया। हालांकि यह महामारी के बाद सबसे कम था। लेकिन रीवा के सुपारी कारीगर इस डेटा का हिस्सा नहीं हैं। इसका एक कारण यह है कि वे पहचान कार्ड योजना से नहीं जुड़े हैं। पहचान कार्ड योजना केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय की ओर से हस्तशिल्प कारीगरों के पंजीकरण और पहचान पत्र प्रदान करने और उन्हें राष्ट्रीय डेटाबेस से जोड़ने की एक पहल है। राकेश ने कहा कि हमें ऐसी किसी भी योजना की जानकारी नहीं है। वे 2021 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए नेशनल हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम का भी हिस्सा नहीं हैं। 2001-02 में शुरू हुई सरकार की अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना भी इसी की एक कड़ी है। लेकिन सुपारी शिल्पकार इसके साथ भी नहीं जुड़े हैं, क्योंकि उन्होंने समुदाय का कोई औपचारिक समूह नहीं बनाया हुआ है।

कई राज्यों तक करते हैं सप्लाई, लाखों रुपए का किसान को रहो मुनाफा

इंदौरी किसान का खुद का हल्दी ब्रांड

महू। जागत गांव हमार

करने कुछ गए थे, हो कुछ गया, लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ। ऐसा ही कुछ हुआ है इंदौर के एक किसान के साथ। उसने फायदे के लिए अंबाडी की खेती शुरू की, लेकिन अंबाडी की फसल ने हल्दी की फसल के लिए कीटनाशक का काम किया। इससे उसका लाभ बढ़ गया। **'जागत गांव हमार'** के इस अंक में बता रहे हैं इंदौर के सिमरोल निवासी किसान जितेंद्र की कहानी। जितेंद्र पाटीदार बताते हैं कि दो साल पहले की बात है। मैं पारंपरिक तरीके से खेती कर रहा था। ज्यादातर हल्दी की पैदावार करता था, लेकिन हल्दी में लगे कीट मेरी फसल का काफी हिस्सा चट कर जाते थे। मैं ऐसी फसल खोज रहा था, जिससे मेरे लिए लाभ का सौदा बन जाए, तभी मेरे एक दोस्त ने बताया कि अंबाडी की खेती कर। मैंने इंटरनेट पर सर्च किया तो पता चला इसके पत्ती से लेकर जड़ तक बिकती है। फिर आत्मा की शर्ली थॉमस से बात की तो उन्होंने बताया कि इसके फूलों से जैम बनता है, जो महंगे दामों पर बिकता है।

फूलों पर मरे पड़े थे व्हाइट फ्लाई

मुझे लगा कि यही अंबाडी की खेती नुकसान को फायदे में बदल सकती है। शुरुआत में तय किया इसे कम हिस्से में प्रयोग के तौर पर लगाऊंगा। मैंने इसे हल्दी की फसल के साथ ही लगा दिया। अंबाडी के पौधे बड़े होने लगे। एक दिन जब मैं इसके फूलों को देखने लगा तो उसमें मुझे हल्दी के लिए हानिकारक कीट (व्हाइट फ्लाई) मरे मिले। फिर गौर किया तो पता चला इस बार हल्दी की फसल को कम नुकसान हुआ है। मुझे यकीन नहीं हुआ तो अगली बार हल्दी के फसल के बीच में अंबाडी के पौधे लगाए तो नतीजा पहले जैसा ही मिला। अंबाडी अब हमारे लिए कीटनाशक का काम कर रहा था। अब मैं हर फसल के बीच में अंबाडी लगाता हूं, जिससे कीटनाशक की जरूरत नहीं पड़ती है।

प्राकृतिक खेती ने बढ़ाई आय

जितेंद्र पाटीदार बताते हैं कि मैं खेतों में केमिकल-यूरिया का उपयोग करता था। 2016-17 में मैंने पद्मश्री सुभाष पालेकर का प्राकृतिक खेती का शिविर अटेंड किया। पालेकर को भारत में प्राकृतिक खेती का जनक कहा जाता है। उनके शिविर के बाद मेरी रुचि जैविक खेती की ओर बढ़ी। इसके बाद मैंने अपने एक एकड़ खेत में उपलब्ध सामग्री और पशुधन से मिले गोबर, गौमूत्र और छाछ से जीवामृत घन, जीवामृत, डी-कंपोजर जैविक कीटनाशक का उपयोग करना शुरू किया। इसके अच्छे परिणाम मिले तो धीरे-धीरे खेतों में से केमिकल का उपयोग करना कम कर दिया। कुछ मात्रा में रासायनिक खाद और कुछ कंपोस्ट खाद मिलाकर में फसल लेने लगा। इसके साथ ही फंगीसाइड के स्थान पर मैंने मित्र फफूंद व शुष्क जीवियों का सहारा लिया, जिसके चमत्कारिक परिणाम मिले। मैं अब 6 एकड़ में हल्दी की जैविक खेती कर रहा हूं, जिससे हर साल 9 से 10 लाख रुपए का मुनाफा हो रहा है। इसके साथ ही मेरे ब्रांड से 15 से 20 लोगों को रोजगार भी मिल रहा है।

हल्दी बेचकर कमा रहे मुनाफा

जितेंद्र बताते हैं कि अंबाडी के पौधों से होने वाले फायदों को देखते हुए मैंने अपने खेत पर हल्दी की 6 तरह की वैरायटी लगाई। हर किस्म की अलग खासियत होती है। इन फसलों के उपयोग में किसी प्रकार के केमिकल का उपयोग नहीं करता हूं। आर्गेनिक हल्दी होने के कारण इसे ऊंचे दाम पर बेचता हूं, जिसे लोग आसानी से खरीदते हैं। इस तरह से मेरी आमदनी भी बढ़ गई है। इसके बाद मैंने दालों की खेती शुरू की, जिसे तुअर, उड़द और मूंग दाल लगाई है। मैं अपनी आधी जमीन पर प्राकृतिक खेती करता हूं, बाकी आधी जमीन धीरे-धीरे केमिकल मुक्त हो रही है। आर्गेनिक तरीके से पैदा किए गए उत्पादों को मैं अपने ब्रांड शगुन नेचुरल के माध्यम से ही बेचता हूं। इस ब्रांड की ख्याति गुजरात, राजस्थान, मुंबई, देहरादून और पुणे जैसे शहरों में फैल गई है। अब हमारे पास इतने ऑर्डर है कि इसकी सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं।

केंचुआ खाद मददगार

जितेंद्र ने बताया कि मैंने हल्दी की फसल के लिए ढेंचा (केंचुआ खाद) का उपयोग किया। इससे नाइट्रोजन की पूर्ति प्राकृतिक रूप से हुई। यूरिया पर मेरी निर्भरता भी खत्म हो गई। इतना ही नहीं जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़कर 1त्न तक पहुंच गया, जिससे शुष्मजीव की उपलब्धता सहज रूप से फसलों को होने लगी। इससे हुआ यह कि फसल पर लगने वाले कीट भी ढेंचा की ओर आकर्षित हुए। जब इसे हल्दी की फसल के बीच मल्च किया, तो इसके नीचे केंचुओं की पर्याप्त मात्रा खेत में हो गई, जिसने धरती की नीचे पाए जाने वाले पोषक तत्वों को ऊपर लाने का काम किया। खेत में लगे पौधों की जमीन को चारों तरफ से ढेंचा से कवर किया जाता है। कवर करने के तरीके को पलवार या मल्च कहा जाता है।

2021-22 में मुख्यमंत्री पुरस्कार मिला

जितेंद्र पाटीदार ने बताया कि मेरे इस प्रयोग को आसपास के किसानों के साथ ही कृषि वैज्ञानिकों ने भी खूब सराहा। इस प्रयोग से मैंने रासायनिक खाद के बराबर प्रोडक्शन किया। इसी प्रयोग के चलते मुझे 2021-22 में आत्मा ने मध्यप्रदेश में सर्वोच्च कृषक का मुख्यमंत्री पुरस्कार (51 हजार रुपए) दिया गया। इसके साथ ही 15 अगस्त आजादी के अमृत महोत्सव पर इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह और गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा से भी सम्मान प्राप्त हुआ।

सब्जियों की खेती से 17 परिवारों को रोजगार

एक कैंप... और खूबचंद्र बन गए आत्मनिर्भर किसान

शहडोल। जागत गांव हमार

शहडोल जिले के किसान खूबचंद्र पटेल ने खेती की उन्नत तकनीक अपना कर न सिर्फ अपने आप को मालामाल किया, 17 परिवारों को रोजगार भी दे रहे हैं। वे फल, सब्जी की खेती कर हर साल सात लाख रुपए तक मुनाफा कमाते हैं। बबलू के पिता मोहनलाल पटेल गृह ग्राम सिंदूरी में अपनी पुश्तैनी सात एकड़ जमीन में धान और सब्जी की पारंपरिक तरीके से खेती करते थे। इसमें उन्हें सालाना 50 से 60 हजार मिलते थे, उसमें सिर्फ जीवनयापन ही हो पाता था। बबलू सात साल पहले किसान मित्र बने। मंडला के किसान को उन्नत तकनीकी से खेती करते देखा। अब वे ड्रिप सिंचाई, फलदार पौधों के लिए स्टैंड, सीजन पर सबसे पहले सब्जी व फल की पैदावार से वे अच्छा मुनाफा कमा रहे थे।

पहले साल में तीन गुना कमाई

उन्नत तकनीकी की जानकारी लेकर अपने गांव सिंदूरी में पुश्तैनी जमीन पर खेती की। मेहनत ज्यादा और खर्च करीब दोगुना हुआ, लेकिन पहले साल ही कमाई में तीन गुना अंतर आ गया। बबलू ने बताया कि उनकी पुश्तैनी सात एकड़ जमीन एक साथ नहीं है। ऐसे में ड्रिप सिंचाई सहित अन्य नवाचार करना संभव नहीं था। उन्होंने चार साल पहले 20 एकड़ जमीन ठेके पर ली। यहां सब्जी उगाना शुरू की। इससे शानदार नतीजे मिले। अब वे संपन्न किसान बनते जा रहे हैं। आसपास के जरूरतमंद लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं।

परवल की खेती ने दिलाई पहचान

पांच साल पहले बबलू के पिता मोहनलाल के बिहार के रहने वाले एक मित्र ने परवल की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्हें परवल की कुछ बेल दीं। इनको बबलू ने अपने गांव के खेतों में लगाया, चूंकि उन्नत खेती का तरीका उन्हें पहले से पता था तो यह बेल खूब फली। 5 डिसमिल जमीन में उन्होंने 10 हजार की परवल की बेलें उगाईं। चार साल से वे ठेके पर जमीन लेकर पांच एकड़ में परवल उगाते हैं। इसे 3 से 4 लाख रुपए में बेचते हैं। परवल के मामले में वे क्षेत्रीय किसानों के लिए प्रेरणा के रूप में उभरे हैं। उन्हें देखकर और उनसे सीखकर जिले के लमरो, मझगवां, खोड़हाल, चुनिया, पचगांव, मझौली, शाहपुर, खम्हरिया, सिंदूरी, ऐंताझर, केलमनिया जैसे कई गांवों के किसानों ने परवल उगाया।

स्वस्थ्य मृदा संरक्षण के लिए विश्व मृदा दिवस का आयोजन

मृदा में कार्बनिक पदार्थ-पोटाश की मात्रा जिलें में कम हो रहा

नरसिंहपुर। जागत गांव हमार

कृषि विज्ञान केन्द्र नरसिंहपुर में विश्व मृदा दिवस का आयोजन ग्राम सिवनी बंधा के सरपंच नेबूलाल गौड़ की अध्यक्षता एवं केन्द्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. विशाल मेशराम के मार्गदर्शन में किया गया। कार्यक्रम में केन्द्र के वैज्ञानिक डॉ. एसआर शर्मा ने मृदा में उपस्थित 17 तत्वों के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए उनके उपलब्धता एवं महत्व के बारे में किसानों को अवगत कराया। डॉ. शर्मा द्वारा यह भी बताया गया कि मृदा में कार्बनिक पदार्थ तथा पोटाश की मात्रा जिलें में कम हो रहा है। जिसकी आपूर्ति के लिए प्राकृतिक एवं जैविक पदार्थों का प्रयोग मृदा में करना अति आवश्यक है। जिसके लिए किसान पौधों के अवशेष, पशुओं के गोबर, मल-मूत्र एवं हरी खाद का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि मृदा में पोषक तत्वों का उपयुक्त स्तर नहीं होने की स्थिति में अनुशंसित मात्रा के अनुसार देशी गोबर खाद 8-10 टन एवं केचुओं 4-5 टन प्रति हेक्टेयर वर्ष में 1 बार या उपलब्धता के अनुसार प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार अनिवार्य रूप से प्रयोग करें। गोबर खाद पूर्ण रूप से पकी होनी चाहिए, नहीं तो यह मृदा एवं पौधे को नुकसान पहुंचाती है। डॉ. विशाल मेशराम ने बताया कि प्राकृतिक खेती अपनाकर हम मृदा स्वस्थ्य रखने के साथ ही वातावरण में प्रदूषण की मात्रा भी कम कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती से प्राप्त उत्पाद मनुष्य एवं पशुओं के स्वास्थ्य के लिए लाभकर होगा। इसके लिए अन्य आर्गेनिक पदार्थों के साथ ही जब गोबर की खाद का उपयोग करते हैं, तो यह उपयोगी सूक्ष्म जीवों के विकास को बढ़ावा देता है। मृदा में नमी रखता है और जमीन में पानी की सही मात्रा को बनाये रखने के लिए मिट्टी की क्षमता को बढ़ाता है। यह सब तभी संभव है जब खाद पूरी तरीके से विघटित (कम्पोस्ट) हो जाए। कार्यक्रम में केन्द्र के वैज्ञानिक डॉ. निधि वर्मा, डॉ. विजय सिंह सूर्यवंशी तकनीकी सहायक रिंकी झारिया के साथ ही 39 किसानों की सरायनीय उपस्थिति रही।

-कुलपति बोले-कृषक भगवान तुल्य, जो धरा का रखते हैं ध्यान

जनजातीय विवि में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की होगी स्थापना

अनूपपुर। जागत गांव हमार

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक के कृषि विज्ञान केंद्र गत दिवस विश्व स्वास्थ्य मृदा दिवस क्षेत्र के किसानों को प्रशिक्षित कर मनाया गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष कुलपति प्रो. प्रकाश मणि त्रिपाठी एवं मुख्य अतिथि शीला त्रिपाठी (अध्यक्ष-शील मंडल) उपस्थित रहीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कुलपति ने कहा की धरती हमारी मां है और हम सब इसके बच्चे। अत: हमें अपनी मां का ध्यान रखना चाहिए। आज का दिन इस बात का द्योतक है कि हम उस धारा के प्रति चिंतित रहें जो हमें जीवन पर्यन्त अन्न देती है। उसके प्रति हमें सम्मान करना चाहिए। धरा के ऊपर कृषक भगवान तुल्य हैं, जो धरा का ध्यान रखते हैं और यह रेवा खंड तो ईश्वर की तपोभूमि यहां के कण-कण में भगवान हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र में एक ऊत और आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित प्रयोगशाला जल्द ही बनाई जाएगी इसका मैं आश्वासन देता हूं।

किसानों को दिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड

कार्यक्रम में किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए जिसके द्वारा किसान संतुलित मात्रा में उर्वरकों का उपयोग कर मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाए रखेंगे। मुख्य अतिथि शीला त्रिपाठी ने कहा कि धरती एक मां की तरह है, जिस तरह जन्म देने वाली मां के शरीर को पोषक तत्व दिए जाते हैं ताकि आने वाली संतान हष्ट-पुष्ट हो। ठीक इसी तरह धरती में भी हमें पोषक तत्व डालने चाहिए ताकि उन्नत फसल हमें मिल सके।

मृदा परीक्षण की दी जानकारी

मंच का संचालन एवं कार्यक्रम के सहसंयोजक संदीप चौहान ने किया। अंत में डॉ. अनिल कुर्मी द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया गया। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक सुनील कुमार राठौर द्वारा किसानों को कृषि से संबंधित तकनीकी जानकारी दी गई। कार्यक्रम संयोजन डॉ. अनीता ठाकुर ने किया एवं किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना एवं मृदा परीक्षण के बारे में जानकारी दी गई।

प्रतियोगिता में विजेता छात्र-छात्राओं को दिए पुरस्कार

चित्रकूट ग्रामोदय विवि में जैविक खेती के किसानों को बताए फायदे

चित्रकूट। जागत गांव हमार

महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्व विद्यालय के अन्तर्गत कृषि संकाय के प्राकृतिक संसाधन विभाग द्वारा कृषि संकाय के कृषि वैज्ञानिकों एवं विभाग के छात्र एवं छात्राओं द्वारा 5 दिसम्बर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया गया। जिसके अन्तर्गत मृदा को स्वस्थ्य कैसे रखा जाए इस पर कृषि वैज्ञानिक डॉ. उमाशंकर मिश्र प्राकृतिक खेती के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा मृदा को स्वस्थ्य रखने के लिए मृदा के चारों घटक खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, जल एवं वायु को जैविक पदार्थों के द्वारा संतुलित रखते हुए मृदा के भौतिक गुणों रासायनिक गुणों, जैविक गुणों एवं उर्वरता गुणों में सुधार करते हुए मृदा को स्वस्थ्य रखते हुए अनाज, फल एवं सब्जियों के गुणवत्ता को बनाए रखा जा सकता है।

दुष्परिणाम भी किसानों को बताए

डॉ. सुधाकर प्रसाद मिश्र ने कहा उर्वरकों, कीटनाशक, एवं शाकनाशी रासायनिक पदार्थों के प्रयोग के दुष्परिणाम के बारे में बताया। कृषि संकाय के अधिष्ठाता प्रो. केके सिंह 1960-70 के दशक के दौरान कृषि में होने वाली समस्याओं एवं उनके निराकरण पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर उन्होंने देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के योगदान पर भी प्रकाश डाला।

प्रतियोगिता का आयोजन

विश्व मृदा दिवस जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रतियोगिता आयोजित किया गया। पुरस्कार वितरण किया गया। जिसके अन्तर्गत हर्ष गुप्ता एवं भारती एमएससी कृषि (मृदा विज्ञान) के छात्र को प्रथम पुरस्कार, शिखा एवं साक्षी एमएससी कृषि (मृदा विज्ञान) को द्वितीय पुरस्कार एवं अभिषेक एवं कृतिका को तृतीय पुरस्कार से अधिष्ठाता कृषि संकाय द्वारा सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में शोध छात्र ओपेन्द्र कुमार सिंह, आशुतोष मिश्र, अनीसा, वीरेन्द्र कुमार पटेल, विवेक कुमार सिंह, और मिश्रा ने भाग लिया।

कृषि विज्ञान केंद्र में विश्व मृदा दिवस मनाया

हर संभव संसाधन संरक्षण तकनीकी का प्रयोग करें

रीवा। कृषि विज्ञान केन्द्र रीवा में विश्व मृदा दिवस का आयोजन अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय रीवा डॉ. एसके पयासी की उपस्थिति व कृषि विज्ञान केन्द्र रीवा के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. एके पांडेय के मार्गदर्शन मे किया गया। वर्ष 2022 की थीम 'मृदा: जहां से भोजन प्रारंभ होता है' रही। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि डॉ. एसके पयासी ने किया। उन्होंने छात्रों-कृषकों से आग्रह किया कि वे केंद्र सरकार की मंशानुरूप अपने मृदा के स्वास्थ्य व उर्वरता में सुधार लाने के लिए हर संभव संसाधन संरक्षण तकनीकी का प्रयोग करें व मृदा को जीवित बनाए रखें। हरी खाद के साथ-साथ खेत के अवशेषों के प्रबंधन की आवश्यकता पर जोर दिया। जिससे मृदा मे कार्बनिक प्रदार्थों के स्तर और मृदा की जल धारण क्षमता को बढ़ाया जा सके। कार्यक्रम के तकनीकी सत्र में मृदा स्वास्थ्य व पोषक तत्व प्रबंधन के विषय में तकनीकी जानकारी देते हुए पौध संरक्षण वैज्ञानिक के डॉ. एसके त्रिपाठी ने विभिन्न प्रकार की मृदाओं के संरक्षण की विधियों पर प्रकाश डाला। डॉ. आईएम खान ने विश्व मृदा दिवस के इतिहास एवं महत्व पर रोचक जानकारी दी एवं डॉ. पी पेराजू ने समन्वित खेती की उन्नत तकनीको का मृदा संरक्षण में महत्व पर प्रकाश डाला।

भोजन का 95 फीसदी मिट्टी से मिलता है

डॉ. किजलक सी सिंह प्रसार वैज्ञानिक ने इस अवसर पर जानकारी देते हुए बताया कि हमारे भोजन का 95 प्रतिशत मिट्टी से उत्पन्न होता है। डॉ. संजय सिंह, प्रसार वैज्ञानिक ने मृदा को टिकाऊ व स्वस्थ एवं उपजाऊ बनाने के लिए अवश्यक जैव उर्वरक, केचुआ खाद फसल अवशेष प्रबंधन आदि विषयों पर तकनीकी जानकारी दी।

यह भी रहे मौजूद

केन्द्र के खाद्य वैज्ञानिक डॉ. चंदजीत सिंह, उद्यानिकी वैज्ञनिक डॉ. राजेश सिंह, एमके मिश्रा एवं मौसम पर्यवेक्षक मंजू शुक्ला भी उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का संचालन कृषि संकाय की चतुर्थ वर्ष की छात्रा रिया कुमारी ने किया। कार्यक्रम के अंत में डॉ. संजय सिंह ने आभार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में ब्रजेश सेन, ऋषभ विश्वकर्मा एवं दीवान का सक्रिय सहयोग रहा।

मिट्टी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी

अशोकनगर। स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र अशोकनगर में विश्व मृदा दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. बीएस गुप्ता द्वारा मृदा स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करते हुए किसानों से आग्रह किया कि मिट्टी एक जीवित माध्यम है। इसमें असंख्य सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं और उनकी चयापचय क्रियाओं के माध्यम ह्यूमस का निर्माण होता है, जिससे पेड़ पौधे में पत्तियां शाखाएं फल-फूल आदि का निर्माण होता है। अत: हमें मिट्टी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। रासायनिक दवाओं एवं उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग के कारण हमारी जमीन एवं प्राकृतिक संसाधन दूषित होते जा रहे हैं। मानव प्रजाति तथा पशुओं के ऊपर इसके दुष्प्रभाव हो रहे हैं। बहुत सारी बीमारियां बहुत तेजी से हमारे जीवन में पैर पसार रही हैं। अत: इन दुष्प्रभाव से बचने के लिए रासायनिक खेती के स्थान पर कुछ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती प्रारंभ करें, जिससे हम अन्नदाता के साथ-साथ विस रहित भोजन भी समाज को प्रदान कर सकें।

पौध संरक्षण पर जोर

केंद्र के वैज्ञानिक हेमंत कुमार त्रिवेदी ने जैविक तरीके से पौध संरक्षण उपाय अपना सकते हैं की विस्तृत जानकारी प्रदान की। मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला से शैलेंद्र पुरोहित ने मिट्टी परीक्षण एवं मिट्टी के नमूना लेने की विधि के बारे में जानकारी प्रदान की।

जैविक विधि से अच्छा उत्पादन

बचने के लिए प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर होना बहुत जरूरी है। डॉ. केके यादव द्वारा उद्यानिकी फसलों में किस प्रकार से हम जैविक विधि के माध्यम से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं जानकारी दी गई। मौसम वैज्ञानिक इंदें सिंह मिर्धा ने मौसम के बारे में जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉ. ममता सिंह, डॉ. वैशाली शर्मा, डीपी सिंह, उप परियोजना संचालक जितेन्द्र सिंह राजपूत, वरिष कृषि विकास अधिकारी एसके जैन आदि ने भी इस अवसर पर मृदा स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न तकनीकी बिन्दुओं पर प्रशिक्षण प्रदान किए।

विश्व मृदा दिवस किसानों को दिया प्रशिक्षण

सागर। कृषि विज्ञान केन्द्र सागर में विश्व मृदा दिवस का आयोजन डॉ. दिनकर प्रसाद शर्मा संचालक विस्तार सेवाएं के निर्देशन में किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ. एमपी दुबे एवं अध्यक्षता संयुक्त संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग बीएल मालवीय ने किया। इस कार्यक्रम में वैज्ञानिक, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं किसानों सहित कुल 69 से अधिक लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम का आयोजन डॉ. केएस यादव, प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मृदा स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न बिन्दुओं जैसे मिट्टी का नमूना लेने के तरीके एवं संतुलित उर्वरकों का उपयोग, प्राकृतिक एवं जैविक उर्वरकों का मृदा सुधार में प्रमुख भूमिका, समसामयिकी विषयों जैसे गेहूं, चना, मसूर इत्यादि में खाद उर्वरकों का संतुलित उपयोग, खरपतवार नियंत्रण एवं कृषकों द्वारा उठायीं गईं विभिन्न समस्याओं का समाधान भी कृषि वैज्ञानिकों एवं अधिकारियों द्वारा किया गया।

तकनीकी प्रशिक्षण दिया

कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉ. ममता सिंह, डॉ. वैशाली शर्मा, डीपी सिंह, उप परियोजना संचालक जितेन्द्र सिंह राजपूत, वरिष कृषि विकास अधिकारी एसके जैन आदि ने भी इस अवसर पर मृदा स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न तकनीकी बिन्दुओं पर प्रशिक्षण प्रदान किए।

इस बार जिले के किसानों ने गेहूं से ज्यादा सरसों पर दिया ध्यान

श्योपुर में 58 हजार सरसों, 43 हजार हेक्टेयर में गेहूं की बोवनी

शिवपुरी/श्योपुर। खेमराज मौर्य

श्योपुर जिले में अभी तक जिलें में 58 हजार 500 हेक्टेयर में सरसों की बोवनी हो चुकी है। गेहूं की बोवनी 43 हजार 600 हेक्टेयर में ही हो पाई है। किसानों के द्वारा गेहूं की जगह सरसों की बोवनी ज्यादा करने के पीछे कारण यह है कि, पिछले दो तीन सालों से सरसों के दाम में बढोत्तरी हुई है। इसलिए ज्यादातर किसानों ने गेहूं की जगह सरसों की बोवनी की है। इस बार कृषि विभाग ने रबी फसलों की बोवनी का लक्ष्य 1 लाख 68 हजार हेक्टेयर में किए जाने का तय किया था। इसमें गेहूं की बोवनी का रकवा 75 हजार हेक्टेयर, सरसों की बोवनी का रकवा 60 हजार हेक्टेयर और चने की बोवनी का रकवा 30 हजार हेक्टेयर निर्धारित किया था। चूंकि गत वर्ष जिलें के किसानों ने गेहूं से ज्यादा ध्यान सरसों पर दिया है। गत वर्ष जिलें में सरसों की करीब 57 हजार हेक्टेयर में सरसों की बोवनी हुई थी, इसलिए कृषि विभाग ने इस साल सरसों का रकवा बढाकर 60 हजार हेक्टेयर तय किया है। कृषि विभाग के अधिकारियों की माने तो अभी तक जिले में रबी फसल की बोवनी का काम लगभग 78 प्रतिशत कंपलीट हो चुका है। यानि एक लाख 31 हजार हेक्टेयर में रबी फसलों की बोवनी हो चुकी है। इसके तहत 58 हजार 500 हेक्टेयर में सरसों की बोवनी हो चुकी है। जो लक्ष्यपूर्ति के नजदीक है। जबकि गेहूं की बोवनी 43 हजार 600 हेक्टेयर और चने की बोवनी 26 हजार हेक्टेयर में हो गई है। जौ, मटर, मसूर आदि फसलों की बोवनी भी 80 फीसदी से ज्यादा हिस्से में हो गई है।

रबी फसल की बोवनी का काम लगभग 78 प्रतिशत कंपलीट हो चुका है। शेष बोवनी का काम भी जल्द पूरा हो जाएगा। क्योंकि गेहूं की बोवनी का काम चल रहा है। इस साल किसानों ने सरसों पर ज्यादा ध्यान दिया है।
-पी गुजरे, उप संचालक कृषि, श्योपुर

सरसों में लागत कम, किसानों को मुनाफा ज्यादा

सरसों के भाव में तेजी होने के चलते इस साल समूचे क्षेत्र में सरसों की बुआई काफी ज्यादा हुई है। जिले में सरसों का रकबा बीते वर्ष की तुलना में काफी बढ़ गया है। किसानों का कहना है कि सरसों में लागत कम और मुनाफा ज्यादा है। क्योंकि सरसों का भाव 6500 के आसपास चल रहा है। जबकि गेहूं का भाव 2500 के आसपास ही है। जबकि लागत और मेहनत गेहूं में ज्यादा है।

रबी फसलों की बोवनी की स्थिति एक नजर में

फसल	लक्ष्य	बोवनी	गतवर्ष बोवनी
गेहूं	75000	43600	77500
सरसों	60000	58500	57350
जौ	7500	7000	7400
चना	30000	26300	27430
मटर	4500	3000	4500
मसूर	1900	1300	1900
अलसी	2200	1800	2100
गन्ना	70	50	70
अन्य	2300	2100	2310
योग	168980	131860	166025

विश्व मृदा दिवस पर प्रधान वैज्ञानिक डॉ.सिंह बोले

धरती का ध्यान नहीं रखा तो बंजर हो जाएगी जमीन

लहार। जागत गांव हमार

धरती हमारी माता है। माता रूपी इस धरती अर्थात मिट्टी का यदि इस समय ध्यान न रखा तो आने वाले कुछ वर्षों में मृदा अपनी उपजाऊपन को खो देगी। इसलिए यह उचित समय है कि किसान मिट्टी की पोषणता को बनाए रखने के लिए उसके स्वास्थ्य पर ध्यान दें। यह बात कृषि विज्ञान केन्द्र में आयोजित विश्व मृदा दिवस के अवसर पर केन्द्र के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. एसपी सिंह ने कही। उन्होंने बताया कि पौधों को 16 पोषक तत्वों की जरूरहत होती है, जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एवं पोटाश तीन प्रमुख पोषक तत्व हैं। इसके अलावा जिंक, आयरन, गंधक जैसे अन्य पोषक तत्व की पौधों को अपनी बढ़वार अच्छी उपज देने आदि के लिए आवश्यकता होती है। परन्तु जिले के सभी विकासखंडों की जांच के बाद यह बात उभरकर सामने आई है कि जिले की मिट्टी में नाइट्रोजन, गंधक, जिंक जैसे पोषक तत्वों के अलावा ऑर्गेनिक कार्बन जैसे प्राकृतिक रूप से मिलने वाले तत्वों की कमी देखी जा रही है।

खेत रेत बन रहे

डॉ. सिंह ने कहा कि जीवाश्म की कमी के कारण जलधारण क्षमता प्रभावित होने के साथ ही खेत रेत बन रहे हैं। जमीन के अंदर वायु का प्रवेश नहीं हो रहा है। इसलिए किसानों को खेती में ऑर्गेनिक जीवाश्म बढ़ाने की जरूरत है। कार्यक्रम में केन्द्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. अवधेश सिंह द्वारा मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए फसल चक्र अपनाने तथा समय-समय पर मिट्टी की जांच कराने के लिए प्रोत्साहित किया।

जीवामृत का करें प्रयोग

वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. कर्णवीर ने उद्यानिकी फसलों में मृदा के महत्व के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने उद्यानिकी फसलों में प्राकृतिक खेती के घटक जीवामृत जैसी खादों का प्रयोग करने की सलाह दी। केन्द्र के वैज्ञानिक डॉ. रुपेन्द्र सिंह, डॉ. एनएस भदौरिया ने भी संबोधित किया।

नवनियुक्त कुलपति मिश्रा पहली बार पहुंचे रीवा, किया आह्वान

हमें सामनाकरना होगा भविष्य में कृषि में होने वाली चुनौतियों से

रीवा। जागत गांव हमार

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर मप्र के नवनियुक्त कुलपति प्रो. प्रमोद कुमार मिश्रा का कृषि महाविद्यालय एवं कृषि विज्ञान केन्द्र, रीवा के प्राध्यापकों, कर्मचारियों एवं श्रमिकों द्वारा प्रथम आगमन पर स्वागत किया गया। इस अवसर पर अध्यक्षता करते हुए कृषि महाविद्यालय के अधिष्ठाता प्रो. एसके पयासी द्वारा मुख्य अतिथि प्रो. पीके मिश्रा कुलपति जवाहरलाल नेहरू कृषि विवि ,जबलपुर मप्र को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। साथ ही कॉलेज मे होने वाली विभिन्न गतिविधियों के विषय से अवगत कराया। कुलपति ने कृषि महाविद्यालय एवं कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों द्वारा किए जा रहे शिक्षण, शोध एवं प्रसार कार्य में किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों की सराहना की और कहा की भविष्य में कृषि में होने वाले चुनौतियों से सामना करने के लिए प्रध्यापकों एवं वैज्ञानिकों को इस प्रकार से कार्य करना है कि छात्रों एवं कृषकों की समस्याओं को समय पर हल किया जा सके। कृषि विज्ञान केन्द्र में केन्द्र प्रमुख डॉ. एके पांडेय एवं वैज्ञानिकों द्वारा कुलपति का स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रो. आरके तिवारी ने किया।

कृषि विज्ञान केन्द्र पन्ना ने बताई विधि

कम लागत में बढ़ जाएगी किसानों की आमदनी

पन्ना। कृषि विज्ञान केन्द्र पन्ना द्वारा विश्व मृदा दिवस पर कार्यक्रम का अयोजन किया गया। कार्यक्रम में लागत में कमी कर कैसे आमदनी बढ़ाई जा सकती है। उनके द्वारा कृषकों को प्राकृतिक खेती के बारे में विस्तार से बताया गया।

प्राकृतिक खेती के घटकों यथा जीवामृत, घनजीवामृत, बीजामृत, नीमास्त्र, बृह्मास्त्र, बनाने के बारे में विस्तार से बताया गया। कार्यक्रम के अंत में रबी फसलों की समसामयिकी पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में कृषि समिति के अध्यक्ष मिजाजीलाल

पटेल एवं समर्थन संस्था से प्रदीप, धरम, सहित गांव के 52 प्रगतिशील कृषकों ने भाग लिया।

केवीके में एग्री इनोवेटर्स और स्टार्टअप जागरूक कार्यक्रम का आयोजन

कृषि व्यवसायिक रूप देने करनी होगी हमें कड़ी मेहनत

टीकमगढ़। कृषि विज्ञान केन्द्र टीकमगढ़ में एग्री इनोवेटर्स और स्टार्टअप जागरूक कार्यक्रम का आयोजन प्रधान वैज्ञानिक डॉ. बीएस किरार के मार्गदर्शन में किया गया। कार्यक्रम में जवाहरलाल नेहरू कृषि विवि, जबलपुर के एग्री बिजनेस प्रबंधन संस्थान से सहायक प्रबंधक लक्ष्मी मनोज सिंह और बिजनेस एक्सीक्यूटव दीपांषू पटेल मौजूद रहे। स्टार्टअप जागरूक कार्यक्रम में किसानों एवं छात्र-छात्राओं को कृषि से संबंधित स्टार्टअप कार्यक्रमों एवं जवाहर एग्रीबिजनेस इनक्यूलेटर कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्रदान की। साथ ही बताया के कृषि कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आरकेव्हीवाय-

राफतार एग्री बिजनेस की स्थापना 2018-19 में देश के 29 केन्द्रों की गई थी। यह कार्यक्रम जनेकृ विवि में जवाहर रबी के नाम से वर्ष 2019 चालू किया गया। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत कृषि संबंधित उद्योग पशुपालन, सांख्यिकी, डेयरी विकास, कृषि वानिकी, कृषि विपणन आदि कृषि संबंधित क्षेत्र से संबंधित कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। केन्द्र प्रमुख डॉ. बीएस किरार ने बताया कि स्टार्टअप कार्यक्रम से कृषि व्यवसायिक रूप देने के लिए कड़ी मेहनत और भविष्य में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए अहम भूमिका साबित होगी। इसके द्वारा व्यवसायीकरण से किसानों को अपनी आय बढ़ाने, खेती में लागत कम करने उत्पादकता बढ़ाने तथा कृषि में ऊर्जा के उपयोग के अनुकूलन में सहायता मिलेगी।

प्रदेश में 7,775 करोड़ के निवेश से मिलेगा 5,350 लोगों को रोजगार

रॉक फॉस्फेट से खाद बनाने के संयंत्र लगाने के कार्य को मिलेगी रफ्तार

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से निवास पर समत्व भवन में विभिन्न निवेशकों ने भेंट कर निवेश प्रस्तावों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेश की दृष्टि से मध्यप्रदेश एक आदर्श राज्य बना है। राज्य सरकार की नीतियों के अनुरूप निवेशकों को पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाएगा। निवेशकों से भेंट और चर्चा के फलस्वरूप प्रदेश में रॉक फास्फेट से खाद निर्माण की इकाई प्रारंभ करने के कार्य को गति मिलने की राह खुली है। नवीन औद्योगिक निवेश प्रस्तावों के फलस्वरूप प्रदेश में 7 हजार 775 करोड़ रुपए का निवेश और 5 हजार 350 लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री से निवेशकों की भेंट के दौरान औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के प्रमुख सचिव मनीष सिंह और मध्यप्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एमडी मनीष सिंह भी उपस्थित थे।

झाबुआ-सागर में स्थापित होगा प्लांट- मुख्यमंत्री से इंडियन फॉस्फेट लि. के प्रबंध संचालक रविंदर सिंह ने भेंट कर बताया कि उनका संस्थान प्रदेश के झाबुआ जिले के मेघनगर में लगभग 200 करोड़ की लागत से संयंत्र की स्थापना कर रहा है। इससे मध्यप्रदेश में किसानों को एसएसपी और डीएपी के लिए अन्य प्रदेशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सिंगल सुपर फॉस्फेट के संयंत्र से स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इंडियन फॉस्फेट लिमिटेड सागर जिले में डीएपी प्लांट के लिए भी निवेश कर रहा है। झाबुआ और सागर के संयंत्र में लगभग 400 लोगों को रोजगार भी देंगे।

2500 लोग रोजगार से जुड़ेंगे

मुख्यमंत्री से मेसर्स ग्रीनको ग्रुप के प्रबंध संचालक अनिल कुमार चलमलाशेट्टी ने भेंट की। बताया गया कि नीमच जिले के गांधी नगर में 1440 मेगावाट का पम्पड स्टोरेज प्लांट लगाया जा रहा है, जिस पर 7200 करोड़ लागत व्यय आएगा। प्रदेश में हॉइड्रो पावर को बढ़ावा देने की यह महत्वपूर्ण परियोजना है। इस संयंत्र के शुरू होने से विद्युत दरों में उल्लेखनीय कमी की भी संभावना है। ग्रीनको ग्रुप की सहयोगी कम्पनी पनारी एनर्जी द्वारा पन्ना में पम्प स्टोरेज के प्रोजेक्ट के लिए इच्छुक है। इससे लगभग 2500 लोग रोजगार से जुड़ेंगे।

प्राथमिकता में फूड पार्क

मुख्यमंत्री से आईटीसी लिमिटेड के पदाधिकारी वदीराज कुलकर्णी और रजनीकांत राय ने भेंट कर सीहोर जिले के औद्योगिक क्षेत्र बड़ियाखेड़ी में 250 करोड़ रुपए के नए निवेश के संकल्प से अवगत करवाया। इससे करीब 200 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री ने आईटीसी लिमिटेड के आवश्यक रियायतें प्रदान करने के आग्रह पर राज्य शासन द्वारा पूर्ण सहयोग और फूड पार्क के कार्य को प्राथमिकता देने की अपेक्षा की।

आदिवासी होंगे लाभान्वित

मुख्यमंत्री से मेसर्स सिद्धायु लाइफ साइंसेज के प्रबंध संचालक प्रणव शर्मा ने भेंटकर छिंदवाड़ा जिले में खैरीटेगांव में निर्माण इकाई के संकल्प की जानकारी दी। जड़ी-बूटियों से दवाओं के निर्माण के लिए करीब 125 करोड़ रुपए की लागत से शुरू होने वाली इकाई से जनजातीय वर्ग को विशेष रूप से लाभ होगा। इस इकाई से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर 2250 लोग लाभान्वित होंगे।

38 साल से विभाग में नहीं हुई भर्ती

बंद होने के कगार पर मप्र भू-संरक्षण विभाग

भोपाल। जमीन का कटाव रोकना, बीहड़ों का समतलीकरण करवाना, मेड़बंधान करना, कच्चे-पक्के नालों में चेक डैम बनवाना, वाटरसेड के काम पौधारोपण आदि के लिए 60 के दशक में खुला भू-संरक्षण विभाग अब बंद होने के कगार पर है। विभाग में 1984 के बाद यानि की 38 साल से विभाग में सर्वेयर की भर्ती ही नहीं हुई है। हालांकि एसएसटी वर्ग के कुछ पदों पर भर्ती जरूर हुई लेकिन यह नाकाफी साबित हुई। कर्मचारियों के लगातार सेवानिवृत होने के कारण अगले तीन वर्षों में विभाग पर ताला लटकने की नौबत नजर आ रही है। कर्मचारी सेवानिवृत हो रहें है लेकिन उनके बदले उन पदों पर भर्ती नहीं हो रही है। विभाग को पिछले 10 सालों से कोई काम भी नहीं मिला है। एक तालाब का काम पिछले साल विभाग को काम के नाम पर केवल बलराम योजना के तहत एक तालाब बनाने का काम मिला है। इस योजना के तहत किसान की भी भूमि पर तालाब बनाया जाता है। इस योजना में सामान्य वर्ग को 80 हजार तथा एसएसीएसटी वर्ग को 1 लाख रुपए मिलते हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि वर्ष 2012 से विभाग के पास काम नहीं है। विभागीय काम पंचायतों को सौप दिए गए है।

विभाग में पर्याप्त स्टाफ भी नहीं

भू-संरक्षण विभाग ग्वालियर में वर्ष 2012 में विभाग के पास 12 सर्वेयर तथा 5 एसडीओ थे। जबकि वर्तमान में 1 एसडीओ और 3 सर्वेयर ही काम कर रहे हैं। इस माह दिसम्बर में मौजूदा एसडीओ तथा एक सर्वेयर भी सेवानिवृत हो जाएंगे। विभाग 20 से 25 फीसदी स्टाफ के साथ ही चल रहा है।

बीहड़ में समतलीकरण की जरूरत

ग्वालियर चंबल संभाग के भिंड और मुरैना के अलावा शिवपुरी जिले में स्थित बीहड़ों के समतलीकरण की अभी भी जरूरत बनी हुई है लेकिन भू संरक्षण विभाग के खत्म होने के बन रहे आसार से बीहड़ों का समतलीकरण भी अधर में लटक जाएगा। अकेले भिंड जिले में करीब 1000 से अधिक हेक्टेयर बीहड़ को समतल किया जा सकता है वहीं मुरैना और शिवपुरी जिले में 2500 हेक्टेयर भूमि समतल हो सकती है लेकिन सरकार की ओर से भू संरक्षण विभाग को अस्तित्व में बनाए रखने के प्रति की जा रही अनदेखी के चलते यह कार्य अब अधर में ही अटके नजर आ रहे हैं। वर्तमान समय में भूमि संरक्षण को लेकिर गंभीरता बरतने की आवश्यकता है। दस्यु उन्मूलन के बाद बीहडों के समतलीकरण का काम तेज होना चाहिए।

-5 जनवरी 2023 को मतदान, 10 को आएगा परिणाम

पंचायतों के आम/उप चुनाव का निर्वाचन कार्यक्रम घोषित

भोपाल। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों के आम/उप निर्वाचन वर्ष 2022 उत्तरार्ध के लिए निर्वाचन कार्यक्रम घोषित कर दिए हैं। मतदान 5 जनवरी 2023 को सुबह 7 से अपरान्ह 3 बजे तक होगा। पंच पद के लिए मतदान मत पत्र एवं मत पेटी के द्वारा तथा सरपंच, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य के लिए मतदान ईवीएम से होंगे। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग राकेश सिंह ने जानकारी दी है कि निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन तथा नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने का कार्य 15 दिसम्बर, 2022 से शुरू होगा। नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 22 दिसंबर है। नाम निर्देशन-पत्रों की जांच 23 दिसंबर को होगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 26 दिसंबर है। इसी दिन निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन भी होगा। मतदान 5 जनवरी को होगा। पंच पद के लिए मतगणना, मतदान समाप्ति के तुरंत बाद मतदान-केन्द्र में ही होगी। सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य की मतगणना 9 जनवरी को सुबह 8 बजे से विकासखंड मुख्यालय पर ईवीएम से होगी। सरपंच तथा जनपद पंचायत सदस्य के परिणाम 9 जनवरी को और जिला पंचायत सदस्य के परिणाम 10 जनवरी को घोषित होंगे।

कितने पद के लिए चुनाव

पंच के 61 हजार 936 पद के लिए उप निर्वाचन और 1364 पद के लिए आम निर्वाचन होगा। सरपंच के 122 पद के लिए उप निर्वाचन एवं 78 पद के लिए आम निर्वाचन होगा। जनपद पंचायत सदस्य के 9 पद के लिए उप निर्वाचन होगा। संबंधित क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है।

कृषि मंत्री पटेल श्रीमद् भागवत कथा में हुए शामिल

भोपाल। किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने हरदा और प्रदेश की धर्म-प्रेमी जनता से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर पुण्य-लाभ अर्जित करने का अनुरोध किया। विख्यात कथा वाचिका जया किशोरी के मुखारबिंद से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का हरदा में बुधवार को शुभारंभ हुआ। कथा आरंभ के पूर्व नगर में कलश-यात्रा निकाली गई। इसमें महिलाओं-बच्चों सहित हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। कृषि मंत्री पटेल ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा आगामी 13 दिसम्बर तक जारी रहेगी। समापन अवसर पर सामूहिक कन्या विवाह के आयोजन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे।

नल से जल पहुंचाने वाले प्रमाणिक गांवों में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर

भोपाल। नल से जल पहुंचाने वाले प्रमाणिक गांवों में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। जल जीवन मिशन में अब तक सात हजार 62 गांवों के प्रत्येक परिवार को नल से जल उपलब्ध कराया जा चुका है। प्रदेश के 54 लाख 86 हजार से अधिक ग्रामीण परिवारों के घर पर नल कनेक्शन से जल उपलब्धता सुनिश्चित की जा चुकी है। 50 हजार करोड़ रुपए की लागत की जल प्रदाय योजनाओं पर काम किए जा रहे हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मिशन के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य में 45.69 प्रतिशत उपलब्धि अर्जित की जा चुकी है। देश में 20 लाख से अधिक वार्षिक लक्ष्य वाले 12 बड़े राज्यों में प्रदेश दूसरे स्थान पर है। ग्रामीण क्षेत्र में संचालित 41 हजार 373 आंगनबाड़ी और 71 हजार 423 शालाओं में नल कनेक्शन से जल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है। अब तक चार हजार 277 गांवों में 100 से 90 प्रतिशत, दो हजार 89 गांवों में 90 से 80 प्रतिशत, एक हजार 595 गांवों में 80 से 70 और 14 हजार 921 गांवों की जल प्रदाय योजनाओं के काम 70 से 60 प्रतिशत प्रगति पर हैं।

-राज्यपाल बोले-अधिनियम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति अनुरूप संशोधन करें

सरकारी और निजी विवि हर साल पांच-पांच गावों को लें गोद

भोपाल। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा है कि सभी निजी और शासकीय विश्वविद्यालय अधिक से अधिक रोजगारमूलक पाठ्यक्रम संचालित करें। पाठ्यक्रमों की उच्च गुणवत्ता के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि दीक्षांत समारोह में निजी कंपनी और उद्योगों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाए। कुलपति का नाम कुलगुरू किए जाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्यपाल राजभवन के सांदीपनि सभागार में समन्वय समिति की 100वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि शासकीय और निजी विवि हर वर्ष 5-5 गांव गोद लेकर स्वास्थ्य, स्वच्छता और सामुदायिक सेवा के कार्यों का संचालन करें। राष्ट्रीय सेवा योजना और सामुदायिक सेवा के कार्यों के समान ही रेडक्रॉस सोसायटी के साथ समन्वय कर, मानवता की सेवा के कार्यों में योगदान दें। प्रधानमंत्री ने नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा युवाओं को जमीन से जुड़े रहते हुए अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम बनने का अवसर दिया है। नीति के प्रभावी और एकीकृत क्रियान्वयन के लिए विश्वविद्यालय अधिनियमों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप संशोधन का कार्य समय-सीमा में पूरा किया जाए।

विवि बनाएं पहचान

उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि विवि काम के आधार पर पहचान बनाएं। विवि क्षेत्रीय संसाधन और संभावनाओं से संबद्ध जैसे वनांचल में वन, दर्शनीय क्षेत्रों में पर्यटन संबंधी और औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों के अनुरूप पाठ्यक्रम संचालित करें। विश्वविद्यालय में किए जा रहे उत्कृष्ट कार्य, नवाचार और बौद्धिक सम्पदा से समाज को परिचित कराएं।

सीएम शिवराज ने कहा-प्रदर्शनियों से किसानों को मिलेगी जानकारी

किसानों को आधुनिक कृषि का प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा

भोपाल। जागत गांव हमार

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में किसानों को आधुनिक कृषि का प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा। विशेष प्रदर्शनियों से नवीनतम कृषि उपकरण और अद्यतन तकनीक से किसानों को अवगत करवाया जाएगा।

किसानों के कल्याण के अधिकतम कार्य कैसे किए जाएं, इसके लिए निरंतर चिंतन चल रहा है। कृषक कल्याण प्राथमिकता है। इस कार्य में मुझे किसानों का सहयोग भी चाहिए। जिलों में ऐसी बड़ी प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी, जिनमें आधुनिकतम कृषि उपकरणों का प्रदर्शन होगा। इनके अवलोकन से किसान प्रशिक्षित होंगे और कृषि कार्य को आसान बना सकेंगे। किसान नई कृषि तकनीक की जानकारी लेकर आम के आम गुठलियों के दाम सिद्धांत पर अधिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे। मुख्यमंत्री किसान गौरव सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन में प्रदेश के जिलों से आए किसान बंधुओं ने हिस्सा लिया।

प्राथमिकता में किसान

मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक खेती का प्रशिक्षण भी किसानों को मिलना चाहिए। प्रदेश में प्राकृतिक कृषि को अपनाने में भी किसान रुचि व्यक्त कर रहे हैं। प्रदेश में किसानों से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता से लागू किया जा रहा है। इस सिलसिले में ऐसे कृषक परिवार, जिनके पास बाप-दादा के जमाने से एक या दो एकड़ राजस्व भूमि है और जिसमें वे कृषि कर रहे हैं तथा वे सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के हैं, उनके पुराने प्रकरण में पट्टा देने पर विचार किया जाएगा।

ट्रांसफार्मर पर मिलेगा अनुदान

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ट्रांसफार्मर के लिए अनुदान की योजना पूर्व सरकार ने बंद कर दी थी जिसे पुन: प्रारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना भी प्रारंभ होगी। इसके अलावा कपिलधारा योजना का प्रभावी क्रियान्वयन होगा। किसानों के सुझाव पर आगामी बजट में किसानों के लिए आवश्यक राशि के प्रावधान होंगे।

65 लाख हेक्टेयर सिंचाई का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के हित के लिए मध्यप्रदेश में निरंतर कार्य किया गया है। अंग्रेज और नवाबों के शासन और पूर्व की सरकारों के प्रयासों को मिला कर वर्ष 2003 तक प्रदेश में सिर्फ 7 लाख 50 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में ही सिंचाई क्षमता विकसित हुई थी, वर्तमान में सिंचाई क्षमता बढ़ कर 45 लाख हेक्टेयर हो गई है। अब इसे 65 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाने का लक्ष्य है। प्रदेश के प्रत्येक इलाके में सिंचाई योजनाएं लागू हैं। सिंचाई क्षमता के विस्तार का कार्य लगातार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान निधि के साथ मुख्यमंत्री किसान-कल्याण योजना की राशि भी किसानों को दी जा रही है। उन्हें कार्यक्रम कर लाभान्वित किया जा रहा है। पूर्व सरकार ने ब्याज माफी की घोषणा की थी, लेकिन किया कुछ नहीं। अब राज्य शासन ने कर्ज के ब्याज की राशि को माफ करने का निर्णय लिया है।

शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण मिल रहा

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलवाना राज्य सरकार का लक्ष्य है। किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। किसानों को समारोहपूर्वक राशि अंतरित की जाएगी। बिजली की सब्सिडी पर बड़ी राशि राज्य सरकार खर्च कर रही है। इसकी निरंतर मॉनीटरिंग की जाती है। किसान भी योजनाओं के अमल में कहीं गड़बड़ हो तो उसकी जानकारी से अवगत करवाएं।

किसान भी रखें नजर

किसान सिंचाई योजनाओं को देखने जाएं। यह देखें कि नहरों की मरम्मत हो रही है या नहीं। खेतों में टेल एंड तक पानी पहुँचे, यह हम सभी का कर्तव्य है। किसानों को पर्याप्त पानी मिले, इसे सुनिश्चित करें। प्रदेश के बांधों में पर्याप्त जल राशि मौजूद है। काफी बड़े बजट को खर्च कर योजनाएं बन रही हैं। सिंचाई के लिए पाइप लाइनें बिछाई जा रही हैं। किसान क्षेत्र का भ्रमण कर सिंचाई संबंधी कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करें। सिंचाई से जुड़े निर्माणाधीन कार्यों पर निगाह रखें।

किसानों के हित में संगठन करें काम

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान संगठन द्वारा जले ट्रांसफार्मर बदलने के कार्य में भी दायित्व निर्वहन किया जाए। संगठन के सदस्य इस दिशा में सजग रहें और ट्रांसफार्मर से जुड़ी व्यवस्थाओं को देखें। किसान संगठन तभी उपयोगी और प्रासंगिक हैं जब किसानों के हित में वे काम आएं। इससे बड़ी संतोष की कोई बात नहीं होती है कि हम दिल से लोगों की सेवा करें और किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का कार्य करें। तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। किसान संगठन के अध्यक्ष दर्शन सिंह ने कहा कि प्रदेश के किसान प्राकृतिक खेती के लिए आगे आ रहे हैं। गौ-पालन को महत्व दे रहे हैं। मप्र को 7 कृषि कर्मण अवार्ड मिले हैं।

भिंड में कृषि विज्ञान केंद्र खोलने से किसान होंगे आत्मनिर्भर

-भिंड-दतिया सांसद संध्या राय ने लोकसभा में रखा प्रस्ताव

भोपाल। जागत गांव हमार

भिंड-दतिया भाजपा सांसद संध्या राय ने भिंड जिले में एक और कृषि विज्ञान केंद्र खोलने के लिए लोकसभा में केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित कराते हुए कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र खोलने से भिंड जिले के किसानों को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा और वह आत्मनिर्भर विकास की मुख्यधारा से किसान जुड़ सकेंगे। अभी तक लहार विधानसभा में कृषि केंद्र स्थापित है। अन्य विधानसभाओं के किसान लहार नहीं पहुंच पाते हैं। इससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सांसद ने लोकसभा की शीतकालीन सत्र की कार्यवाही के दौरान कहा कि पूर्व में भी कृषि विज्ञान केंद्र खोलने के लिए मैं अपनी इस मांग को पूर्व में सदन में रख चुकी हूं, लेकिन अभी तक कोई अमल नहीं हुआ है। भाजपा सांसद संध्या राय ने लोकसभा सदन में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि लहार में कृषि केंद्र खोला गया है, जो कि जिला मुख्यालय से 60 किलो मीटर की दूरी पर स्थित है। जबकि अन्य तहसीलों के किसान लहार नहीं पाते हैं। जिला मुख्यालय पर कृषि केंद्र खोलना अति आवश्यक है, जो कि पूर्व में भी मैं ध्यान आकर्षित करा चुकी हूं। अभी तक विचार में नहीं लाया गया है।

कृषि केंद्र साबित होगा वरदान

भिंड जिला कृषि क्षेत्र में उपज के लिए काफी अहम स्थान रखता है। जिले में अतिरिक्त कृषि विज्ञान केंद्र खोला जाए, जो कि भिंड के विकास में एक वरदान साबित होगा। जिले की 5 विधानसभा है और 4 विधानसभाओं के किसानों को योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। अगर दूसरा कृषि केंद्र स्थापित हो जाएगा तो चार विधानसभाओं के किसान योजना का लाभ लेकर आगे बढ़ने का काम करेंगे।

धार में भी खोले गए हैं दो केंद्र

संध्या नेकहा कि प्रधानमंत्री का संकल्प है किसानों की आय दुगनी करना उसमें भी सार्थक होगा। भारतीय अनुसंधान केंद्र द्वारामप्र के धार जिले में 2 कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को लाभ दिलाने के लिए खोले गए हैं। भिंड में भी कृषि भूमि आवंटन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले से ही भवन निर्माण हो चुका है जिस पर सरकार का कोई भार नहीं पड़ेगा। संध्या ने कृषि मंत्री तोमर से मांग की कि लहार भौगोलिक दृष्टि से दूर है जिससे चार विस के किसानों को लाभ नहीं मिल पाता है।

-आयुष राज्य मंत्री कावरे महा-सम्मेलन में कहा

आदिवासी ग्रामों का समग्र विकास सरकार की प्राथमिकता

भोपाल। जागत गांव हमार

आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रामकिशोर कावरे ने कहा है कि प्रदेश के जनजातीय ग्रामों में अधो-संरचना विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राथमिकता से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन ग्रामों का समग्र विकास राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में है। आयुष राज्य मंत्री कावरे बालाघाट जिले के ग्राम विश्रामपुर में जनजातीय महा-सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन भी मौजूद थे। राज्य मंत्री कावरे ने विश्रामपुर में 50 बिस्तर के आयुष अस्पताल का शिलान्यास भी किया। कावरे ने बताया कि जिले के परसवाड़ा में आयुष विभाग द्वारा रिसर्च सेंटर खोला जा रहा है। उन्होंने बताया कि लामता क्षेत्र की 146 करोड़ रुपए की सिंचाई योजना को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना में क्षेत्र के 55 ग्राम में पाइप के जरिये पानी पहुंचाया जाएगा। आयोग के अध्यक्ष बिसेन ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में जनजातीय जन-नायकों को उनकी वीरता की पहचान दिलाने का कार्य किया जा रहा है। इस मौके पर डामरीकृत सड़क और सभा मंच निर्माण का भी भूमि-पूजन किया गया।

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, स्थानीय संपादक- **अरविंद मिश्र, संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)